भारत संघ और अन्य

बनाम

बख्शी राम

मार्च 1,1990

[के. जगन्नाथ शेट्टी, न्यायाधीश और आर. एम. सहाय, न्यायाधीश]

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958: धारा 12-दोषसिद्धि के बाद परिवीक्षा पर रिहाई का दायरा-दोषसिद्धि के कलंक को मिटाता नहीं है-"ऐसे कानून के तहत अपराध की सजा के साथ संलग्न अयोग्यता, यदि कोई हो, नहीं होगी"-अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून द्वारा अयोग्यता को संदर्भित करें।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949: धारा 10 (एन)-आरक्षक- सक्षम बने रहना-अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के प्रतिकूल कार्य करना-दोषसिद्धि

परिवीक्षा पर रिहाई-सेवा से बर्खास्तगी-कहा बहाली का हकदार नहीं-'बर्खास्तगी' के दंड को 'सेवा से हटाने' में बदल दिया गया।

प्रतिवादी, एक सिपाही, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 10 (एन) के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिसने उनकी बहाली का आदेश देते हुए कहा कि उनके लिए सेवा में बने रहने के लिए कोई

अयोग्यता नहीं थी, क्योंकि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 में उनकी दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाने का प्रभाव है। इसलिए भारत संघ की यह अपील।

अपील को अनुमति देते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

1. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 केवल यह निर्देश देती है कि अपराधी को 'ऐसे कानून के तहत अपराध की दोषसिद्धि के साथ जोड़कर, अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करना पड़ेगा।' इस संदर्भ में ऐसा कानून दोषसिद्धि के कारण अयोग्यता का प्रावधान करने वाला अन्य कानून है, उदाहरण के लिए यदि कोई कानून किसी व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि को देखते हुए किसी पद पर नियुक्त करने के लिए या किसी प्राधिकरण या निकाय के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है, तो धारा 12 के आधार पर अयोग्यता हट जाती है। लेकिन यह कहना समान बात नहीं है कि जिस व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वह सदाचरण की परिवीक्षा का लाभ प्राप्त करने पर बहाली का हकदार है। धारा 12 विभाग को कदाचार से होने वाले अपराध या कानून के हिसाब से उसके बाद होने वाली दोषसिद्धि पर कार्रवाई करने से नहीं रोकती है।

इसका उद्देश्य व्यक्ति को विभागीय दंड से दोषमुक्त करना नहीं था। [766 बी-सी; 765 ई]

आर. कुमारस्वामी अय्यर बनाम आयुक्त, नगर परिषद तिरुवन्नमलई और अन्य, **[1957]** क्रि. एलजे 255; एम्बारु (पी) बनाम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, [1963] 1 एल.एल.जे. 49 मैड; ए. सत्यनारायण मूर्ति बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक एल. आई. सी., ए. आई. आर. 1969 ए. पी. 371; प्रेम कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, [1971] प्रयोगशाला & इंड. मामले 823; ओम प्रकाश बनाम निदेशक डाक सेवा और अन्य, [1971] 1 एस. एल. आर. 648 और डाक सेवा निदेशक और अन्य वी. दया नंद, [1972] एस. एल. आर. 325, स्वीकृत।

मण्डल कार्मिक अधिकारी दक्षिण रेलवे और अन्य बनाम टी आर. चलप्पन, [1975] 2 एस. एल. आर. 587, पालन किया।

2. आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि एक बात है और सजा दूसरी। दुराचार के लिए विभागीय सजा अभी भी तीसरी है। न्यायालय अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों को लागू करते समय दोषसिद्धि पर विचार नहीं करती; यह केवल उस सजा पर विचार करती है जिससे अपराधी को गुजरना पड़ता है। अपराधी को सजा सुनाने के बजाय, अदालत उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर देती है। हालांकि दोषसिद्धि अछूती रहती है और दोषसिद्धि का कलंक मिटता नहीं है। विभागीय कार्यवाहियों में दोषी को उस आचरण के आधार पर जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है बर्खास्त या हटाया जा सकता है या रैंक में कम किया जा सकता है। इसलिए प्रतिवादी की सेवा बहाली का सवाल ही नहीं उठता है।

हालाँकि, सेवा से बर्खास्तगी के दंड को सेवा से हटाने में बदल दिया जाता है। [765 सी-डी, एफ; 766 ई]

तुलसी राम पटेल बनाम भारत संघ, [1985] पूरक 2 एससीआर 131 और त्रिखा राम बनाम वी. के. सेठ और अन्य, [1987] पूरक एस. सी. सी. 39, अनुसरण किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1312/1990।

डी. बी. सिविल डब्ल्यू. पी. सं. 71/77 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 6.7.1988 से।

एस. हेगड़े, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ए. सुब्बा राव अपीलार्थियों के लिए सी. वी. एस. राव।

प्रतिवादियों के लिए एस. सी. बिड़ला।

न्यायालय का निर्णय के. जगन्नाथ शेट्टी, न्यायाधीश द्वारा दिया गया। विशेष अनुमति दी गई।

प्रतिवादी बख्शी राम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में राजस्थान के देवली में सिपाही थे।

17 मार्च 1971 को लगभग 8:45 बजे शाम को उन्होंने एक अन्य सिपाही के साथ सी. आर. पी. ग्रुप सेंटर बैंड पलटन के सिपाही गरीब दास के कमरे में जबरन प्रवेश किया। गरीब दास तब कमरे में मौजूद नहीं थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी, जो अंदर थीं, ने उन्हें प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। दोनों सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

प्रतिवादी पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 10 (1) के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। अधिनियम की धारा 10 कम जघन्य अपराधों को निर्धारित करती है और धारा 10 (1) किसी भी कार्य या चेतावनी को संदर्भित करती है, जो हालांकि अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के लिए प्रतिकूल है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर उन्हें आरोप का दोषी पाया गया और 23 मार्च 1971 के फैसले द्वारा उन्हें मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और कमांडेंट समूह केंद्र, सीआरपीएफ, देवली (राजस्थान) द्वारा चार महीने के आर. आई. की सजा सुनाई गई। सजा काटने के लिए उन्हें जयपुर की सिविल जेल में रखा गया था।

उसकी दोषसिद्धि और सजा को देखते हुए, विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई तब की गई जब दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी। विद्वान न्यायाधीश ने 22 सितंबर 1971 के निर्णय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 ("अधिनियम") के तहत रिहा कर दिया। जाहिरा तौर पर उन्हें छह महीने की अवधि के लिए शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए बांड प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 4 के तहत रिहा कर दिया गया था। प्रतिवादी ने उन शर्तों का पालन किया। अच्छे आचरण की अवधि समाप्त होने के बाद, उन्होंने सेवा से उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 पर भरोसा करते हुए बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि उन्हें

सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि प्रतिवादी को बर्खास्त करने का एकमात्र कारण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उसकी दोषसिद्धि थी, लेकिन अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 12 को देखते हुए, उसके लिए सेवा में बने रहने के लिए कोई अयोग्यता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने इस तरह टिप्पणी कीः

> "परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 की धारा 12 की स्पष्ट भाषा यह प्रावधान करती है कि जिस व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के तहत कारवाई हो उसकी किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं होगी, यदि कोई हो, जो किसी भी कानून के तहत दोषसिद्धि से जुड़ी हो, किसी भी अन्य कानून में कुछ भी अंतर्निहित होते हुए भी। सी आर पी एफ अधिनियम की धारा 10 के तहत इस प्रावधान में याचिकाकर्ताओं के दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाने का प्रभाव है। परिवीक्षा अपराधी अधिनियम, 1958 की धारा 12 जो विशेष रूप से इस स्थिति के बारे में है स्पष्ट करता है की इसमें जो प्रावधान हैं, “किसी भी अन्य कानून में कुछ भी अंतर्निहित होते हुए भी" है। इसलिए, उसी को प्रभाव देना होगा।"

उच्च न्यायालय के फैसले को इस अपील में चुनौती दी गई है। चूँकि अपील का परिणाम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के दायरे और अर्थ को बदल देता है, इस धारा को निर्धारित करना आवश्यक है। धारा 12 इन शब्दों में हैः

"12. दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाना-किसी भी अन्य कानून में कुछ भी अंतर्निहित होते हुए भी, कोई व्यक्ति यदि किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि उस पर धारा 3 या धारा 4 के प्रावधान के तहत कारवाई होती है तो कोई भी अयोग्यता यदि हो, लागू नहीं होगी जो ऐसे ऐसे कानून के तहत, किसी अपराध की दोषसिद्धि से जुड़ी हो।

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसको धारा 4 के तहत रिहा होने के बाद, मूल अपराध के लिए सजा सुनाई गई।"

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 अदालत को शक्ति देती है कि चेतावनी के बाद कुछ अपराधियों को रिहा कर दे। धारा 4 न्यायालय को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की शक्ति प्रदान करती है। अदालत द्वारा धारा 4 के तहत किए गए निपटारे के तहत सजा को परिवीक्षा की अवधि के दौरान निलंबित कर दिया जाता है और अपराधी को शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए एक बंधन से सहमत होने पर रिहा कर दिया जाता है। धारा 9 में अपराधी के बांड की शर्तों का पालन करने में विफल रहने के मामले में प्रक्रिया का प्रावधान है। न्यायालय, यदि संतुष्ट हो जाता है कि अपराधी अच्छा व्यवहार रखने के लिए बंधपत्र की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है, तो उसे मूल अपराध के लिए सजा दी जा सकती है या जहां विफलता पहली बार रही है, तो बंधपत्र के

जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय उस पर जुर्माना लगा सकता है जो रु पचास से अधिक का न हो।

इन प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपराधी की परिवीक्षा पर रिहाई दोषसिद्धि के दाग को नहीं मिटाता है। मण्डल कार्मिक अधिकारी, दक्षिणी रेल और अन्य आदि बनाम टी. आर. चलप्पन आदि, [1975] 2 596 पर एस. एल. आर. 587 में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3,4 और 9 के दायरे पर विचार करते हुए फज़ल अली, न्यायाधीश ने इस न्यायालय की ओर से यह टिप्पणी कीः

> "इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि परिवीक्षा पर रिहाई तभी अस्तित्व में आती है जब आरोपी दोषी पाया जाता है और अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। इस प्रकार अभियुक्त की दोषसिद्धि या अदालत का निष्कर्ष कि वह दोषी है, उसे बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अपराधी की परिवीक्षा पर रिहाई या आदेश के लिए यह अनिवार्य शर्त है। परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश केवल न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश के प्रतिस्थापन में। इसको एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ क़ानून द्वारा अनुमेय बना दिया गया ताकि युवा अपराधियों में सुधार लाया जा सके और उन्हें कठोर अपराधी होने से रोका जा सके। अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधान जो ऊपर बताए गए हैं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपराधी का नियंत्रण आपराधिक अदालत द्वारा बनाए रखा जाता है

और जहां यह संतुष्ट होता है कि परिवीक्षा पर रिहा किए गए अपराधी द्वारा बांड की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो अदालत अपराधी को मूल अपराध के लिए सजा दे सकती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपराधिक आरोप पर अपराध का तथ्य केवल अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश पारित करने से दूर नहीं हो जाता है। अधिनियम की धारा 3,4 या 6 के तहत, कलंक जारी रहता है और दुराचार के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि को एक निर्णायक प्रमाण माना जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, इसलिए, हम प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मजिस्ट्रेट का अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दोषसिद्धि के कलंक को मिटा देता है।"

धारा 12 के दायरे के बारे में विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा (596 पर):

"यह सुझाव दिया गया था कि अधिनियम की धारा 12 किसी भी दोषसिद्धि के प्रभाव को पूरी तरह से मिटा देती है और अयोग्यता को दूर कर देती है जो इस तरह के कानून के तहत दोषसिद्धि से जुड़ी हो। यह तर्क, हमारी राय में, संविधान की धारा 12 के प्रावधानों के घोर गलत अध्ययन पर आधारित है, ये शब्द "ऐसे कानून के तहत एक अपराध की सजा के साथ संलग्न," दो संभावनाओं को संदर्भित करती है।

(I) दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अयोग्य ठहराना चाहिए।

(2) और इस तरह की अयोग्यता का प्रावधान अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कानून के अलावा किसी और कानून में होना चाहिए। दंड संहिता में ऐसी कोई अयोग्यता नहीं है। इसलिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम की धारा 12 दोषसिद्धि के साथ एक स्वचालित अयोग्यता और अभियुक्त के आपराधिक दुराचार के उन्मूलन से जुड़ी हुई है । यह भी स्पष्ट है कि अयोग्यता इसके अर्थ में अनिवार्य रूप से 'दुराचार' से अलग है।

आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि एक बात है और सजा दूसरी। दुराचार के लिए विभागीय सजा अभी तीसरी है। न्यायालय अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों को लागू करते समय दोषसिद्धि पर विचार नहीं करता है; यह केवल उस सजा पर विचार करता है जिससे अपराधी को गुजरना पड़ता है। अपराधी को सजा सुनाने के बजाय, अदालत उसे अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहा कर देती है। हालाँकि, दोषसिद्धि अछूती है और दोषसिद्धि का कलंक मिटता नहीं है। विभागीय कार्यवाहियों में अपराधी को उस आचरण के आधार जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है बर्खास्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है या पद को छोटा किया जा सकता है; (संविधान का अनुच्छेद 311 (2) (बी) और तुलसीराम पटेल मामला देखें। [1985] पूरक 2 282 पर एस. सी. आर. 131).

अधिनियम की धारा 12 विभाग को कानून के अनुसार दुराचार के लिए कार्रवाई करने से नहीं रोकती जिससे अपराध या दोषसिद्धि हुई है। इस धारा का उद्देश्य व्यक्ति को विभागीय दंड से दोषमुक्त करना नहीं है। इसलिए उस सेवा में बहाली का सवाल नहीं उठता है, जिससे उन्हें उनकी दोषसिद्धि को देखते हुए हटा दिया गया

था। यह धारा 12 की शब्दावली से स्पष्ट प्रतीत होता है। इस पहलू पर उच्च न्यायालय एक स्वर में बोलता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आर. कुमारस्वामी अय्यर बनाम. आयुक्त, नगर परिषद तिरुवन्नमलई और अन्य, [1957] क्रि. एल. जे. 225 खण्ड 58 और एम्बारु (पी) वी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, [1963] 1 एल. एल. जे 59 मैड., ए. सत्यनारायण मूर्ति बनाम में क्षेत्रीय प्रबंधक, एल. आई. सी., ए. आई. आर. 1969 ए. पी. 371 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रेम कुमार बनाम भारत संघ और अन्य मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, [1971] लैब एंड इंड. मामले 823, ओम प्रकाश बनाम में निदेशक डाक सेवा (डाक और तार विभाग) पंजाब सर्कल, अंबाला और अन्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, [1971] 1 एसएलआर 643, डाक सेवा निदेशक और अन्य बनाम दया नंद में दिल्ली उच्च न्यायालय, [1972] एस. एल. आर. 325 ने भी इसी विचार को व्यक्त किया है। उपरोक्त मामलों में उच्च न्यायालयों के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा टी आर. चलप्पन के मामले [1975] 2 SLR 587 में अनुमोदित किया गया है।

त्रिखा राम बनाम वी. के. सेठ और अन्य, [1987] पूरक एससीसी 39 में इस अदालत ने धारा 12 का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता की सजा को "सेवा से बर्खास्त" करने से "सेवा से हटाने" में बदल दिया है, ताकि यह उसे अन्य प्रतिष्ठानों में भविष्य में रोजगार प्राप्त करने में मदद कर सके।

इस प्रकार धारा 12 स्पष्ट है और यह केवल यह निर्देश देती है कि "ऐसे कानून के तहत अपराध की सजा के साथ संलग्न अयोग्यता, यदि कोई हो, अपराधी पर लागू नहीं

होगी। इस संदर्भ में ऐसा कानून अन्य कानून है जो दोषसिद्धि के कारण अयोग्यता का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कानून किसी व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि को देखते हुए किसी पद पर नियुक्त करने के लिए या किसी प्राधिकरण या निकाय के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है, तो धारा 12 के आधार पर अयोग्यता हट जाती है। वास्तव में यही अधिनियम की धारा 12 का दायरा और प्रभाव है। लेकिन यह कहना एक ही बात नहीं है कि जिस व्यक्ति को उसकी दोषसिद्धि के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वह अच्छे आचरण की परिवीक्षा का लाभ प्राप्त करने पर उसे बहाल किए जाने का हकदार है। जाहीर तौर पर, इस तरह के दृष्टिकोण का धारा 12 की शर्तों द्वारा कोई समर्थन नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया गया है। हालाँकि, हम सेवा से बर्खास्तगी के दंड को 'सेवा से हटाने' में बदल देते हैं जैसा कि त्रिखा राम के मामले में किया गया था।

मामले की परिस्थितियों में, हम हर्जे-खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

टी.एन.ए

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।